HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
(COMMITTEES)
NOTIFICATION

The 19th November, 2015.

No.14/6/2015-3CII :- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, with immediate effect, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification no. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 :-

1. In para 4, for sub paras (ii) and (iii), the following sub-paras shall be substituted namely:-

(ii) A one time rebate of 30% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the year 2010-11 to 2012-13 upto 31.12.2015.

(iii) Those who have already deposited the tax, the excess amount, if any, shall be adjusted against future property tax liabilities without interest provided they clear all the dues including the tax for the year 2015-16 upto 31.12.2015.

2. In para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely :-

"(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5 % per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property Tax pending since years 2010-11 to 2014-15 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31.12.2015.

Dr. Mahavir Singh,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst No. 14/6/2015- 3CII Dated : 20.11.2015

A copy is forwarded to the Controller Printing and Stationery Department, Haryana Chandigarh with the request that the above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra -ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record.

Superintendent Committee-II,
for Principal Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
(समितियां)
अधिसूचना

दिनांक 19 नवम्बर, 2015

संख्या 14/6/2015–3क–II हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां) अधिसूचना संख्या का0 आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां), अधिसूचना संख्या का0 आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में:–

1. पैरा 4 में, उप पैरा (ii) तथा (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरे प्रतिस्थापित किये जायेगें :–

(ii) 30 प्रतिशत की एक मुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुज्ञात की जायेगी, जो वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लिये अपने सभी देय कर/बकाया 31–12–2015 तक चुका देगें ।

(iii) जिन्होने कर पहले ही जमा करवा दिया है, अधिक राशि यदि कोई हो, किसी ब्याज के बिना, उनके भविष्य सम्पत्ति का दायित्वों के विरूद्व समायोजित कर दी जायेगी, बशर्ते वे वर्ष 2015–16 के लिये सम्पत्ति कर सहित, सभी देय 31–12–2015 तक चुका दें ।

2. पैरा 5 में, उप पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:–

"(ख) देर से अदायगी की दशा में, प्रतिमास 1.5% की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जाएगा–परन्तु वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक के लिए सम्पति कर के बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी यदि 31 दिसम्बर, 2015 तक उनके बकाया भुगतान कर दिये जाते हैं ।"

डा0 महावीर सिंह
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ।